

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, नरेगा)



क्रमांक 4(21) आरडी / नरेगा / एमआईएस / 2009-10

जयपुर, दिनांक:- 16/10/09

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2008-09 की सूचनाएँ एमआईएस पर अपलोड करने एवं उन्हें अन्तिम माने जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वित्तीय वर्ष 2008-09 को समाप्त हुए छः माह व्यतीत हो चुके हैं। लेकिन फिर भी समस्त सूचनाओं का इन्द्राज अभी तक एमआईएस पर नहीं हुआ है। जिसके कारण योजना के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगता है एवं भारत सरकार द्वारा भी इस पर कडा रूख लिया गया है।

दिनांक 15.10.09 को एमआईएस पर उपलब्ध डाटा के अनुसार मुख्य बिन्दुओं की स्थिति निम्नानुसार है :-

1. श्रम मद में भुगतान की स्थिति :- जिलो से प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार हुए व्यय एवं एमआईएस पर उपलब्ध व्यय की स्थिति के अनुसार अभी तक कुल 72 प्रतिशत व्यय का इन्द्राज एमआईएस पर किया गया है। झुझुनूं जिले द्वारा जहां सर्वाधिक 88 प्रतिशत व्यय का इन्द्राज किया गया है, वहीं सवाई माधोपुर द्वारा मात्र 43 प्रतिशत व्यय का इन्द्राज किया गया है। जिला डूंगरपुर, जालौर, जोधपुर, चूरू, उदयपुर, पाली, बीकानेर, टोंक, झालावाड, बून्दी, चित्तौडगढ, बांसवाडा, जैसलमेर एवं राजसंमद अन्य जिले हैं जिनमें श्रम मद में व्यय का इन्द्राज राज्य की औसत इन्द्राज से कम है।
2. सामग्री मद में भुगतान :- बडे ही खेद की बात है कि सामग्री मद में मात्र 29 प्रतिशत व्यय का इन्द्राज ही एमआईएस पर किया गया है। जहां सिरोही जिले द्वारा लगभग पूर्ण इन्द्राज किया जा चुका है, टोंक, जैसलमेर, जोधपुर, सीकर, उदयपुर, गंगानगर एवं करौली जिले द्वारा नगण्य राशि का इन्द्राज इस मद में किया गया है। सिरोही, बांरा, कोटा, डूंगरपुर, बीकानेर एवं नागौर जिले को छोडकर शेष सभी जिलों

में सामग्री मद में इन्द्राज 50 प्रतिशत से भी कम है। यह प्रगतिरत एवं पूर्ण कार्यों पर प्रयुक्त सामग्री के बैंक एण्ड बिलिंग को बढ़ावा देता है। एमआईएस पर सामग्री मद में इन्द्राज नहीं करना शंका उत्पन्न करता है। भीलवाड़ा में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में भी यह स्पष्ट हुआ है कि सामग्री मद में बोगस फर्मों से सामग्री क्य कर घालमेल का प्रयास किया जाता है। निकट भविष्य में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव भी होने वाले हैं। अतः सामग्री मद में इन्द्राज और भी आवश्यक हो जाता है। कृपया इस सम्बन्ध में विशेष अभियान चलाया जाकर सामग्री मद में हुए व्यय का इन्द्राज तुरन्त प्रभाव से पूर्ण किया जावे।

3. कुल व्यय :- योजना अन्तर्गत गत वर्ष हुए कुल व्यय का 60 प्रतिशत का इन्द्राज ही एमआईएस पर किया गया है। बांरा एवं सिरोही जिले द्वारा ही लगभग 80 प्रतिशत व्यय का इन्द्राज एमआईएस पर किया गया है। राजसमंद, करौली, झालावाड, टोंक, सीकर, बांसवाडा, जालौर, उदयपुर, चित्तौडगढ, सवाईमाधोपुर एवं जैसलमेर जिलों में एमआईएस पर इन्द्राज राज्य के औसत से कम है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिलो के पास पिछले वर्ष की राशि अवशेष है।
4. रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवारों की संख्या, प्रयुक्त मस्टररोल एवं मानव दिवस सृजन :- प्रगति प्रतिवेदन एवं एमआईएस पर उपलब्ध डाटा के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवारों की संख्या एवं प्रयोग में ली गई मस्टररोल की संख्या का इन्द्राज लगभग पूर्ण हो चुका है, परन्तु फिर भी मानव दिवस सृजन का इन्द्राज मात्र 79 प्रतिशत है। इन तीनों मद में उपलब्ध डाटा के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि मासिक प्रगति प्रतिवेदन में इन तीनों मद में दिये गये डाटा में काफी विरोधाभास है। सिरोही एवं जयपुर जिले में तुलनात्मक रूप से अधिक सही डाटा दिये गये हैं। शेष सभी जिलों में अत्यन्त अंतर पाया गया है। कृपया यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि वर्ष 2008-09 में प्रयुक्त की गई सभी मस्टररोल का इन्द्राज एमआईएस पर किया जा चुका है। कुछ मस्टररोल के इन्द्राज की रेण्डम आधार पर जांच भी कराई जाये ताकि यह भी स्पष्ट हो सके कि मस्टररोल का इन्द्राज पूर्ण रूप से किया गया है। उदाहरण के तौर पर चुरु. ने एमपीआर अनुसार 1.05 लाख मस्टररोल उपयोग में ली गई है जबकि एमआईएस में 1.32 लाख एमपीआर फीड की गई है। इसके विरुद्ध एमआईएस में मानव दिवस सृजन 75 प्रतिशत ही है। इसका अर्थ है कि कहीं त्रुटि हो रही है।

